



तारीख 	हुक्म या फारसनामी गय इन्डिपेंडेंस नज अपील संख्या 95/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00056) बअनवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम इत्यादि	नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
--	---	--

	<p style="text-align: center;">न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर (पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्वाडे आर.ए.एस.)</p> <p style="text-align: center;">सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम</p> <p>उपरिस्थित</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांदस रेस्पोंडेंट एवं उनके अधिवक्ता वावजूद सूचना अनुपस्थित। <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p style="text-align: right;">दिनांक 15 अप्रैल 2025</p> <p>अपीलांदस ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औरियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 271/2013 अगवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम में पारित आदेश दिनांक 17 जून 2016 के विरुद्ध अदालत हांगा के समक्ष दिनांक 12 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की गई।</p> <p>वहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांदस ने वहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 811 रकबा 163.10 बीघा ग्रांग पल्ली प्रथम अपीलांदस की पैतृक खातेदारी की एवं कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलांदस का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त वला आ रहा है। रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से की भूमि खरीद की गई है। रेस्पोंडेंट बिना विधिगत विभाजन करवाये अपीलांदस को मौके से वेदखल कर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को बिना पक्षकारान् को सूचित किये लोक अदालत में रखकर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर अपीलांदस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांदस द्वारा मागले</p>	
---	---	--


तारीख हुण्ड	हुण्ड या कार्यवाही गज इनिशियटिव नज अपील संख्या 95/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00056) यशजवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम इत्यादि	नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुण्ड की तालीम में जारी हुए
----------------	---	--

में जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही प्रार्थना/अपीलांत के कथनों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोंडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांतस की भूमि में देखलंदाजी करने तथा उन्हें वेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अपीलांतस के पक्ष में है।

अंत में अपीलांतस के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांतस स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 को खारिज फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

तहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोषांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.10.2012 के मुताबिक रेस्पोंडेंट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 811 रकबा 163.10 बीघा के सहखातेदार श्रीमती केशरीदेवी धर्मपत्नी धूड़ाराम व धूड़ा पुत्र श्री रतनाराम से उनके नाम दर्ज क्रमशः 1/24 एवं 1/12 वा संपूर्ण हिस्सा की भूमि विशेष भू-भाग दर्शाते हुए खरीद किया जाना पाया जाता है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि को विशेष भू-भाग दर्शाकर क्रय नहीं किया जा सकता है। रेस्पोंडेंटस द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशेष भू-भाग पर कब्जा किया जाता है तो अपीलांतस को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अपीलांतस के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सम्यक सूचना पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलांतस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियटिव नज अपील संख्या 95/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00056) बअनवान सोनाराम व अन्य बनाम पारशराम इत्यादि</p>	<p>नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुक्म की तारीख में जारी हु</p>
------------------------	--	--

	<p>इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के गूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 को अपास्त किया जाकर रेस्पोंडेंट को गूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी में विशिष्ट भू-भाग को स्वयं का वताकर कब्जा करने का प्रयास नहीं करे।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p>	
--	--	--

(ओगप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर